



14 मिनट	8	24	1	GS1 • 3	GS2 • 23	GS3 • 18
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	मेन्स प्रश्न	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 विरोध के बीच लोकसभा में Tribunals Reforms Bill 2026 पास

क्यों ज़रूरी: लोकसभा ने 'ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026' पारित किया है, जिसका उद्देश्य न्यायाधिकरणों (tribunals) की नियुक्तियों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक 'नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन' की स्थापना करना है।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

2 दिल्ली में शेख हसीना के प्रेस इवेंट पर तनाव के बीच दिनेश त्रिवेदी मिले

क्यों ज़रूरी: बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और दिल्ली में शेख हसीना के प्रेस इवेंट को लेकर उत्पन्न तनाव के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध वर्तमान में तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

3 यूएस सीनेट ने रूस और ईरान पर Lindsey Graham के प्रतिबंधों को मंजूरी दी

क्यों ज़रूरी: अमेरिकी सीनेट ने 'लिनडसे ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम' (Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act) को मंजूरी दी है, जो रूसी ऊर्जा के तीसरे देश के आयातकों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

4 लोकसभा ने उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए MDR-free UPI वाला टैक्स बिल पास किया

क्यों ज़रूरी: लोकसभा ने 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' पारित किया है, जिसमें उपभोक्ताओं और लघु व्यापारियों के लिए UPI पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को माफ करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

5 SEBI ने धोखाधड़ी पर एक्शन लिया, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटाए

क्यों ज़रूरी: SEBI, खुदरा निवेशकों को अपजंजीकृत प्रभावशाली व्यक्तियों (influencers) और फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स से बचाने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

विरोध के बीच लोकसभा में Tribunals Reforms Bill 2026 पास

चर्चा में क्यों: लोकसभा ने 'ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026' पारित किया है, जिसका उद्देश्य न्यायाधिकरणों (tribunals) की नियुक्तियों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक 'नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन' की स्थापना करना है।

याद रखें

- Tribunals Reforms Bill, 2026 का उद्देश्य एक National Tribunals Commission की स्थापना करना है।
- राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य (2 न्यायिक, 2 तकनीकी) शामिल होंगे।
- यह विधेयक न्यायाधिकरण नियुक्तियों में दक्षता और स्वतंत्रता में सुधार का प्रयास करता है।

मेन्स कोण भारत में कानून के शासन और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने में न्यायाधिकरण नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100762

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

यूएस सीनेट ने रूस और ईरान पर Lindsey Graham के प्रतिबंधों को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों: अमेरिकी सीनेट ने 'लैंडसे ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम' (Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act) को मंजूरी दी है, जो रूसी ऊर्जा के तीसरे देश के आयातकों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है, जिससे संभावित रूप से भारत प्रभावित हो सकता है।

याद रखें

- Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
- US Senate, United States Congress का उच्च सदन है।
- सदन 31 अगस्त को विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित है।

मेन्स कोण प्रमुख शक्तियों द्वारा लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंधों का भारत जैसे तटस्थ देशों की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100712

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

दिल्ली में शेख हसीना के प्रेस इवेंट पर तनाव के बीच दिनेश त्रिवेदी मिले

चर्चा में क्यों: बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और दिल्ली में शेख हसीना के प्रेस इवेंट को लेकर उत्पन्न तनाव के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध वर्तमान में तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं।

याद रखें

- BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation।
- BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
- तारीक रहमान वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं।

मेन्स कोण हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के आलोक में भारत-बांग्लादेश संबंधों की उभरती गतिशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उनके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100541

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

M

लोकसभा ने उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए MDR-free UPI वाला टैक्स बिल पास किया

चर्चा में क्यों: लोकसभा ने 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' पारित किया है, जिसमें उपभोक्ताओं और लघु व्यापारियों के लिए UPI पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को माफ करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है।

याद रखें

- Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026।
- UPI का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए MDR (Merchant Discount Rate) को माफ कर दिया जाएगा।
- यह विधेयक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और हीरा व्यापार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

मेन्स कोण यूपीआई (UPI) पर एमडीआर (MDR) शुल्क को हटाने और डेटा केंद्रों के लिए कर छूट प्रदान करने से भारत के वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान मिल सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100868

SEBI ने धोखाधड़ी पर एक्शन लिया, 1.2 लाख भ्रामक पोस्ट हटाए

चर्चा में क्यों: SEBI, खुदरा निवेशकों को अपजिकृत प्रभावशाली व्यक्तियों (influencers) और फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स से बचाने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है।

याद रखें

- SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक।
- SEBI के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 62% निवेशक अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से प्रभावित होते हैं।
- SEBI Check और Validated UPI handles भुगतान और ट्रेडिंग ऐप्स को सत्यापित करने के लिए पेश किए गए उपकरण हैं।

मेन्स कोण भारत में खुदरा निवेशकों के संरक्षण पर 'फिनफ्लुएंसर' (finfluencers) और अनियमित ट्रेडिंग ऐप्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। प्रौद्योगिकी-आधारित विनियमन इन जोखिमों को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100858

पुतिन 21 सितंबर के चुनावों के बाद 500,000 नए लड़ाकों को जुटाने की योजना बना रहे हैं

चर्चा में क्यों: यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों और तुर्की के अधिकारियों ने यूक्रेन संघर्ष में रूस द्वारा 500,000 लड़ाकों की संभावित लामबंदी और परमाणु संघर्ष के बढ़ने के जोखिम के प्रति चेतावनी दी है।

याद रखें

- रूस 21 सितंबर के संसदीय चुनावों के बाद 500,000 नए लड़ाकों को लामबंद करने की योजना बना रहा है।
- हकन फिदान वर्तमान में तुर्की के विदेश मंत्री हैं।
- बढ़ते यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, परमाणु हथियारों को 'अंतिम विकल्प' (last resort) के रूप में पहचाना गया है।

मेन्स कोण रूस-यूक्रेन संघर्ष के बढ़ते क्रम वैश्विक सुरक्षा संरचना और परमाणु प्रसार के जोखिम पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100818

Meta का Safe-Harbour स्टेटस रिव्यू के दायरे में, भारत ने मांगी तेज़ टेकडाउन की मांग

चर्चा में क्यों: अल्गोरिद्मिक कंटेंट क्यूरेशन (algorithmic content curation) से संबंधित चिंताओं और अवैध सामग्री को शीघ्र हटाने की आवश्यकता के कारण, भारत सरकार मेटा (Meta) की 'सेफ-हार्बर' (safe-harbour) स्थिति की समीक्षा कर रही है।

याद रखें

- Safe-harbour: उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री (user-generated content) के लिए मध्यस्थों (intermediaries) को देयता से कानूनी सुरक्षा।
- अवैध सामग्री को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित समय सीमा तीन घंटे है।
- Meta: एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह (multinational technology conglomerate) जो Facebook, Instagram और WhatsApp का स्वामित्व रखता है।

मेन्स कोण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए 'सेफ-हार्बर' (safe-harbour) सुरक्षा और अवैध सामग्री को विनियमित करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100768

NRC पहचान पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम से मांगे जवाब

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने 2019 की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र जारी करने से संबंधित याचिकाओं के संबंध में केंद्र और असम सरकार से प्रत्युत्तर मांगे हैं।

याद रखें

- NRC: National Register of Citizens भारतीय नागरिकों की एक सूची है।
- असम: वह राज्य जहाँ भारत में पहली बार NRC लागू किया गया था।
- प्रश्नगत NRC सूची को अगस्त 2019 में अंतिम रूप दिया गया था।

मेन्स कोण राष्ट्रीय लोक रजिस्टर (NRC) जैसी व्यापक पहचान योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/100643

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

असम में बाढ़ से 100 की मौत, 10 जिलों में 1,37,590 लोग विस्थापित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2026 में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत के एंबेसडर ने FCRA संशोधनों का बचाव किया, US के उदाहरण दिए

कावेरी जल संकट: तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी तत्काल सुनवाई, किसान संकट में

कर्नाटक ने लॉन्च किया 'Kudi Balona': 178 सेंटर देंगे प्री-मैरिटल काउंसलिंग सेशन

एडमिरल Krishna Swaminathan ने समुद्री संबंधों के लिए Mauritius की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की

KSEAB डिजिटल सिस्टम लागू करने की तैयारी में

मोदी सरकार में भारत ने जोड़े 11 नए E-Visa एंट्री पॉइंट्स, कुल संख्या हुई 88

40 साल के संबंधों के बीच प्रिंसेस Akiko ने भूटान के Gelephu Mindfulness City का दौरा किया

पंजाब ने वर्कर्स बेनिफिट और स्कूल फीस कैप के लिए बिल पास किए

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कपड़ों को दोष देने की आलोचना की, 2013 के फैसले को बरकरार रखा

तमिलनाडु स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल एडमिशन में 10% आरक्षण की समीक्षा करेंगे

तीस्ता नदी के कटाव और भूस्खलन के कारण NH10 को गंभीर क्षति पहुँची है, जिसके परिणामस्वरूप सि

तेलंगाना लॉटरी खत्म: हैदराबाद में 7,680 सब्सिडी वाले प्लैट्स के लिए आवेदन का आखिरी दिन

भारत ने UNOG को दुर्लभ सफेद मोर दान किया, इंदिरा गांधी की परंपरा को फिर से जीवित किया

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

केरल के मंत्री ने कीटनाशक रिपोर्ट के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की योजना बनाई

SEBI ने Plain-Vanilla Debt Securities के लिए ISIN लिमिट बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव दिया

दुनिया के महासागरों में जुलाई में रिकॉर्ड तापमान दर्ज, तापमान पहुँचा 20.96°C

केरल का एडवांस्ड डिजास्टर सिस्टम फ्लॉड: तकनीक और लागू करने में कमियां पाई गईं

सौराष्ट्र में पहाड़ियों से तट तक स्वतंत्र रूप से घूमते एशियाई शेर

तमिलनाडु CM ने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद किसानों के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान किया

2012 में, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन और सरदार सरोवर नर्मदा निगम

स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों की रोशनी गई, ब्रिटिश स्टार्टअप Siloton ढूँढ रहा है समाधान

पार्लियामेंट्री पैनल ने कश्मीर टूरिस्ट साइट्स के लिए सेंट्रलाइज्ड सर्विलांस की सिफारिश की

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

भारत में कानून के शासन और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने में न्यायाधिकरण नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।